

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1753/2016/भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त-सी, भीलवाड़ा
बनाम

...अपीलार्थी

मै. हमारा पम्प काछोला तह. मांडलगढ़,
जिला भीलवाड़ा

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

...अपीलार्थी की ओर से
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 29/वेट/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-सी, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु पारित आदेश दिनांक 07.04.2015 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत कायम कर रू. 35381/- एवं व ब्याज रू 14,807/- कुल रू 50241/- को अपास्त किया जिससे विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पेट्रोल डीजल एवं ल्यूब्रिकेंट का व्यवसायी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण दिनांक 15.05.2013 को किया जो धारा 22 एवं 24(3) के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण कर दिया गया। आलोच्य वर्ष के कर निर्धारण आदेश में पेट्रोलियम कम्पोजिशन के रिटेल आउटलेट की कम्पोजिशन स्कीम के तहत करारोपण किया गया किन्तु व्यवहारी द्वारा राशि संबंधित वित्तीय वर्ष में समय पर जमा नहीं करवायी। उसके उपरान्त कम्पोजिशन को रेकार्ड की भूल मानते हुए धारा 33 में कम्पोजिशन अस्वीकार कर आदेश पारित कर दिया था जो यह एक सोचा विचार आदेश था। जबकि रेकार्ड की कोई मिस्टेक नहीं है। अतः इसको धारा 33 में पारित नहीं किया जा सकता। व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपरोक्त मांग के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपील स्वीकार की गई जिसके विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
3. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहें। उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

6. विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी पेट्रोल, डीजल एवं ल्यूब्रिकेन्ट का व्यवसायी है। आलोच्य अवधि 2011-12 के कर निर्धारण आदेश में पेट्रोलियम कम्पोजिशन के रिटेल आउटलेट की कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत करारोपण किया गया परन्तु कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.2007 के पैरा सं. 4 (1) के अनुसार कम्पोजिशन फीस 4 त्रैमासिक किस्तों में समय पर जमा नहीं कराई गई तथा राशि समय पर जमा नहीं कराये जाने के कारण स्कीम के पैरा 5(4) के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज एवं लेट फीस के संबंधित वित्तीय वर्ष में भी जमा नहीं करवाई गई जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित आदेश पारित कर करारोपण किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

Taxable turnover	Composition Fee (quarterwise)	Due Date	Deposit Date	Tax @14%	Due tax after deducting of deposits	Interest u/s 55 upto March 2015	Total leviabale amount
273700	300	14.07.2011	28.04.2012	38318	35381	14860/- 42 month	50241/-
	600	14.10.2011	28.04.2012				
	1437	14.01.2012	28.04.2012				
	2937	14.04.2012	09.01.2013				
	2937						

7. अपीलीय अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि एक बार कर निर्धारण अधिकारी ने चेतन्य मस्तिक एवं विवेक के आधार पर अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया है तो उसे धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता।

8. प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया संशोधन किसी प्रकार की त्रुटि सुधार के अन्तर्गत आता है या नहीं।

यह स्पष्ट है कि मूल कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत पात्र मानते हुये कर निर्धारण किया है। उपरोक्त तालिका के कॉलम सं. 3 में अंकित ड्यू दिनांक के विरुद्ध व्यवसायी ने कर कॉलम सं. 4 में अंकित दिनांक को जमा करवाया है जो स्पष्ट रूप से देरी से जमा करवाया गया है।

अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 का संबंधित भाग निम्न प्रकार है:-

Manner of payment of composition amount : -

4.01 The composition amount shall be paid in four quaterly installments. The installment for each quarter shall be paid by 7th day of the immediately succeeding month of the relevant quarter i.e. by July 7th, October 7th, January 7th and April 7th for the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarter respectively. The difference if any, as per the actual turnover of the whole of the year shall be calculated and the halance of the composition amount, if any, shall be April 30th of the immediately succeeding year.

am

5.04 Where a dealer has failed to deposit the composition amount in the period specified under the scheme, he shall be allowed to continue to avail the benefits of the scheme on fulfillment of the following conditions, namely :-

(i) he shall deposit the whole of the amount which has become due under the scheme along with the interest thereon at the rate notified under the said Act; and

(ii) **he shall also deposit a late fee, amounting to twenty five percent of the due composition amount required to be deposited under the scheme where he deposits the due installments within three months of due date, and this late fee shall be fifty percent of due amount if he deposits the due installments after aforesaid period of three months but before March 31 of the relevant financial year, and thereafter he shall not be eligible for the benefits under the scheme.**

Provided where the dealer has furnished the details of the annual turnover to his assessing authority for the period prior to [31-03-2013] and has failed to deposit, composition amount in the period specified under the Scheme or the late fee or interest, if any, before March 31 of relevant year. he shall be allowed to avail the benefit of the Scheme on the condition that he shall deposit a late fee amounting to 100% of due composition amount required to be deposited under the Scheme along with due composition amount and interest up to [September 30th. 2013]

[Provided further that where the dealer who has opted for the Scheme and has failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the Scheme. such dealer shall be allowed to avail the benefit of the Scheme,-

(i) if composition amount and late fee specified under the Scheme for the period after 31-03-2011, has been deposited by him before 31-05-14 and, if he deposits an amount equal to 75% of the composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014; or

(ii) if composition amount specified under the Scheme for the period after 31-03-2011, has been deposited by him but the late fee has not been deposited before 31-05-14, if he deposits an amount equal to 100% of the composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014; or

(iii) for all other dealer, if they deposit, composition amount and an amount equal to 200% of the due composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014]

उपरोक्त विधिक प्रावधान अधिसूचना के बिन्दु सं. 4.01 से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत समस्त किशतों का कर निर्धारित तिथि तक जमा करवाया जायेगा तथा यदि निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करवाया जाता है तो बिन्दु सं. 5.04(ii) के अन्तर्गत कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस जमा करवाकर कम्पोजिशन स्कीम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु इसके बावजूद भी यदि व्यवहारी द्वारा उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं की जाती है तो वह इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा देय कर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाया गया है जिससे बिन्दु सं. 4 का उल्लंघन होना प्रमाणित है। स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। इस प्रकार कर निर्धारण में त्रुटि हुई है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया संशोधन त्रुटि को सुधार की श्रेणी में माना जाना चाहिए।

9. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या यह त्रुटि रिकार्ड पर स्पष्ट दृष्टिगोचर त्रुटि की श्रेणी में आती है या नहीं।

2/12

पैरा सं. 06 में दर्शित तालिका से यह स्पष्ट है कि देय कर निर्धारित तिथि के बाद जमा करवाया गया है जो कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वेट विवरणियों से स्पष्ट हैं। देय कर जमा कराने में विलम्ब हुआ है इस बिन्दु पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी देय कर विलम्ब से जमा होने के कारण प्रश्मन स्कीम का लाभ नहीं दे सकते थे जो कि विधिक प्रावधान कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 5.04 से स्पष्ट है। इस विधिक स्थिति के संबंध में भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इस प्रकार तथ्य व विधिक बिन्दु के संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है जिससे इन्हें डिबेटेबल नहीं माना जा सकता। तथ्य रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हैं। विधिक स्थिति अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 से स्पष्ट दृष्टिगोचर है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर देर से जमा कराने के तथ्य जो कि रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर थे पर ध्यान नहीं दिया व विधिक के उपबन्ध अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के बिन्दु सं. 5.04 की अनदेखी करते हुये कर निर्धारण किया है। विधि के उपबन्धों की अनदेखी (Overlooking a provision of law) रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित त्रुटि की श्रेणी में आती है। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार संशोधित की जाने वाली त्रुटि रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित त्रुटि की श्रेणी में मानी जायेगी।

10. अब इस संबंध में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या धारा 33 के अन्तर्गत ऐसी त्रुटि संशोधनीय है।

राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 निम्न प्रकार है :-

33. Rectification of a mistake. - (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

उपरोक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली त्रुटि को स्वतः या अन्यथा सुधार किये जाने का प्रावधान है। देय कर के संबंध में दायित्व को बढ़ाने का संशोधन धारा 33(5) के अन्तर्गत व्यवहारी को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा समय सीमा 4 वर्ष है। प्रकरण में मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.05.2013 को पारित किया गया है जिनमें संशोधन दिनांक 07.04.2015 को किया गया है जो समय सीमा में है तथा व्यवहारी को नोटिस भी जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार विधिक स्थिति के अनुसार भी रिकार्ड से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।

11. विचाराधीन प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि हुई है जिससे कर अपवचना हुई है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण में धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही की है जबकि इस धारा का Scope बहुत कम है। अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि यदि कर निर्धारण Under Assessed हुआ है तो कर निर्धारण अधिकारी को क्या विधिक उपचार अपनाना चाहिए था। इस संबंध में अधिनियम की धारा 26 पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

26. Escaped assessment.— (1) An assessment —

(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered;
or

(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or

(c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

Explanation.— The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

(2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.

(4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

२०

विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम का लाभ दिया गया है जबकि पैरा सं. 8 में की गई विवेचना के अनुसार लाभ नहीं दिया जा सकता था जिससे राज्य पक्ष को देय कर में कमी हुई है अर्थात् Under Assessment हुआ है। इस धारा 26(c) में **under-assessed in any way or under any circumstances**, शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका यह अर्थ निकलता है कि कम कर निर्धारण किसी भी प्रकार से व किन्हीं भी परिस्थितियों में हुआ है तो इस धारा के अन्तर्गत समय सीमा के उपबन्ध में संशोधित कर निर्धारण किया जा सकता है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अकबरअली अमानतअली बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 10.12.76 (1976 आरएलडब्ल्यू 648) में निम्न प्रकार से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

पैरा 9. Section 12(1) of the Act so far as material reads:

12. Assessment of tax and levy of exemption fee or registration fees incorrectly assessed :
(1) If for any reason the whole or any part of the business of a dealer has escaped assessment to the tax, or if the registration fee or exemption fee has escaped levy or has been assessed at too low a rate in any year, the assessing authority, may serve on the dealer liable to pay the tax in respect of such business or such registration fee or exemption fee a notice in the prescribed form and may proceed to assess or reassess the amount of the tax or levy, the correct amount of registration fee or exemption fee from such, dealer.

पैरा 11. The words 'for any reason' in Section 12(1) of the Act are wide enough and the powers of the Commercial Taxes Officer under the section are not circumscribed by any condition.

इस न्यायिक दृष्टांत में जो कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट 1955 की धारा 12(1) जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के समानान्तर है के संबंध में यह कहा गया है कि " for any reason " शब्दों का Scope काफी अधिक है जो कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों को कम नहीं करती है। धारा 26(c) में तो इससे भी अधिक Scope बनता है क्योंकि इसमें तो **in any way or under any circumstances**, शब्दों का प्रयोग किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत (1973) 32 एसटीसी 223 (आरएचसी) स्टेट ऑफ उडीसा बनाम नन्दासाहू एवं पदमसाहू में पारित निर्णय के संबंधित भाग का उल्लेख करना समीचीन है:-

Section 12 of the Act deals with the procedure for making the assessment. Sub-section (8) deals with escaped assessment of turnover.

Both under the Sales Tax Act as also the Income-tax Act "escaped assessment" has assumed a definite meaning. Escapement of assessment may arise in various circumstances. The dealer may neglect, to make a return or while making a return may suppress a part of the turnover. Even if the turnover has been returned, either by negligence or omission or even by wrong application of law, a part of the turnover may be left out from assessment. Be it on account of the assessee or the assessing officer, if that has ultimately resulted in escapement of a part of turnover from assessment the right to bring the escaped turnover into the net of taxation is vested by a provision like Section 12(8) of the Act in the assessing officer ordinarily subject to limitation as may be prescribed. In such circumstances, merely because a particular information regarding suppression was

already available in the Intelligence Wing before the regular assessment under Section 12(2) of the Act was made and was admittedly not utilised, cannot stand in the way of initiating a proceeding under Section 12(8) of the Act. Even if the information was in the possession of the assessing officer himself, but had not been taken into account in them making of the assessment, the position would not have been different. We have no doubts in our mind that the Tribunal clearly went wrong in using that as a ground for annulling the assessment. The question of law as framed above has to be answered in favour of the taxing department and against the assessee and our answer shall be that in the facts and circumstances of the case, the Tribunal was not right in holding that if particulars of suppression of transaction by the assessee though available at the time of assessment made under Section 12(2) of the Act were not utilised in making the said assessment, proceedings under Section 12(8) of the Act could be taken subsequently on the basis of the very said particulars of suppression.

उपरोक्त धारणा से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विचाराधीन प्रकरण भी Under Assessment की श्रेणी में है तथा इसे Escaped टैक्स मानकर धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मै. जी.एल वुलन्स लि. बनाम राजस्थान राज्य एसबीसीडब्ल्यूपी नं. 3675/2001 निर्णय दिनांक 24.07.02 में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

The expression " In any way or under any circumstances", are the expression which have a very wider connotation. "In any way or under any circumstances" would give all permissible powers to the assessing authority. in that case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone of the existing law, under-assessment is patiently there. therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त से इस धारणा की पुष्टि होती है कि किसी भी कारण से यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर से कम कर का निर्धारण हुआ है तो धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यहा यह उल्लेखनीय है कि यह न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 30 के संबंध में है तथा यह धारा 30 नये अधिनियम राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के बिल्कुल समान है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार विचाराधीन प्रकरण में भी धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1959 एससी 1303 महाराधिराज सर कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:-

"For the reasons we have given, we are of the opinion that the Agricultural Income Tax Officer was competent under Section 29 of the Act to assess an item of income which he had omitted to tax earlier, even though in the return that income was included and the Agricultural Income-tax Officer then thought that it was exempt. the answer given by the High Court was therefore correct."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर भी धारा 26 के अन्तर्गत under assessed कर निर्धारण को पुनः संशोधित किया जा सकता है। अब इस

2/11/

संबंध में समय सीमा के संबंध में विचार किया जाता है। उपरोक्त धारा 26(1)(सी) के प्रावधानानुसार यदि कर Under Assessed हुआ है तो कर निर्धारण अधिकारी उसे धारा 26(3) में दी गई समय सीमा के अन्तर्गत कर निर्धारण कर सकता है। धारा 26(3) में समय सीमा कर निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि से नोटिस जारी करने की पाँच वर्ष व अंतिम आदेश पारित करने की समय सीमा 8 वर्ष है। धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु 33(4) के अन्तर्गत समय सीमा आदेश पारित करने की तिथि से 4 वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष 2011-12 का आदेश दिनांक 15.05.13, में संशोधन हेतु नोटिस दिनांक 19.09.14 को जारी किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी को कर अपवंचना का ज्ञान होने पर कार्यवाही 19.09.14 को प्रारम्भ की गई है तथा उस समय यदि कर निर्धारण अधिकारी धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करते तो भी समय सीमा के अन्तर्गत थी। इस प्रकार प्रकरण में यह अधिक विधिसम्मत होता यदि वे धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करते।

12. प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अपडेट पेज 353) पर विचार किया जाता है। इस न्यायिक दृष्टांत में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी का वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण करते हुये यह ठहराया कि थर्मोवेअर व वेक्यूमवेअर पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत कर देय हैं क्योंकि वे प्लास्टिक गुड्स से भिन्न हैं। कर निर्धारण अधिकारी ने परिमाणस्वरूप 2 प्रतिशत अधिक कर निर्धारण करते हुये सरचार्ज, ब्याज व शास्ति आरोपित की। व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29.03.05 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये 2 प्रतिशत अधिक का कर निर्धारण, ब्याज व शास्ति की मांग निरस्त कर दी। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 13.05.08 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये उपायुक्त (अपील्स) का निर्णय निरस्त कर दिया व कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा। व्यवहारी ने इस आदेश के संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष रेक्टिफिकेशन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निर्णय दिनांक 22.01.09 द्वारा शास्ति इस आधार पर अपास्त कर दी कि व्यवहारी की कोई दुर्भावना नहीं थी व शेष आदेश यथावत रखा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिविजन पिटीशन राज्य पक्ष द्वारा दायर की गई जो निर्णय दिनांक 03.05.10 द्वारा इस आधार पर खारिज की गई कि प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु निहित नहीं हैं। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दायर की गई जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.03.11 द्वारा स्वीकार की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि रेक्टिफिकेशन के द्वारा वही त्रुटि संशोधित की जा सकती है जो रिकार्ड से स्पष्ट होती हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जब माननीय कर बोर्ड ने शास्ति के संबंध में आदेश पारित कर दिया था उस पर रेक्टिफिकेशन के आधार पर पुनर्विचार कर संशोधित नहीं किया जा सकता। विचाराधीन प्रकरण के तथ्य इस न्यायिक दृष्टांत से भिन्न हैं क्योंकि इस न्यायिक दृष्टांत

में व्यवसायी द्वारा कर निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने के कारण प्रश्मन स्कीम का लाभ देय नहीं होने का बिन्दु था तथा कर देर से जमा कराने व इस आधार पर प्रश्मन स्कीम का लाभ देय नहीं होने का बिन्दु स्पष्ट था इन पर विवाद की कोई स्थिति नहीं थी। न्यायिक दृष्टांत में शास्ति देय है या नहीं, यह बिन्दु डिबेटेबल था तथा एक बार जब माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय में शास्ति को यथावत रख दिया था तो फिर रेक्टिफिकेशन के आधार पर संशोधित किया जाना सुविचारित निर्णय को पुर्नविचार करने के समान हैं जबकि विचाराधीन प्रकरण में कर जमा कराने में देरी व उसके कारण पात्र नहीं होने का बिन्दु रिकार्ड व विधिक तथ्यों से स्पष्ट था तथा कर निर्धारण अधिकारी से यह चूक हुई कि उन्होंने विधिक प्रावधान को तथ्यों के संदर्भ में लागू नहीं करने की भूल की। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह बिन्दु नहीं था कि व्यवहारी कम्पोजिशन स्कीम का पात्र है या नहीं। व्यवहारी ने जैसी कर विवरणियां प्रस्तुत की उन पर यथावत विश्वास करते हुये स्वीकार कर लिया जबकि वास्तव में विवरणियों के आधार पर ही व्यवहारी कम्पोजिशन स्कीम का पात्र नहीं बनता था। इस प्रकार यह त्रुटि रिकार्ड से परिलक्षित थी न कि सुविचारित निर्णय के परिणामस्वरूप।

13. कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 07.04.15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने इनपुट टैक्स के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है जबकि कर निर्धारण कम्पोजिशन स्कीम के तहत नहीं किया जाकर सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत किया है जिसमें इनपुट टैक्स दिये जाने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में इनपुट टैक्स के संबंध में कोई ऑकड़ें प्रस्तुत नहीं किये हैं फिर भी प्रत्यर्थी इनपुट टैक्स के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

14. अधीनस्थ न्यायालय अपीलीय अधिकारी ने धारा 33 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं माना है परन्तु प्रकरण में तालिका से यह स्पष्ट है कि देय कर निर्धारित तिथि के बाद जमा करवाया गया है जो कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वेत विवरणियों से स्पष्ट हैं। देय कर जमा कराने में विलम्ब हुआ है इस बिन्दु पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी देय कर विलम्ब से जमा होने के कारण प्रश्मन स्कीम का लाभ नहीं दे सकते थे जो कि विधिक प्रावधान कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 5.04 से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरणों में कर अपवंचना हुई है। व्यवहारी को भी इनपुट टैक्स का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय धारा 26 की समय सीमा भी कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध थी। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण में त्रुटि हुई है तथा कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं होने के बावजूद भी

कर निर्धारण कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत हुआ है जिससे कर अपवंचना का प्रकरण बनता है परन्तु मात्र इस आधार पर कि कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधित कर निर्धारण धारा 33 के अन्तर्गत किया है, व्यवहारी को देय कर से मुक्त नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार यदि प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कर अपवंचना व व्यवहारी के इनपुट टैक्स के बिन्दु का निर्धारण हो सकता है जो अधिक विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

15. परिणामतः राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 83(10) के अन्तर्गत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.16 एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07.04.15 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करें तथा व्यवहारी को पुनः अपनी रिटर्न आदि प्रस्तुत करने का अवसर देकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। यहा स्पष्ट किया जाता है कि धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय धारा 26 की समय सीमा भी कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध थी तथा उसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न न्यायिक स्तरों पर विचाराधीन रहे है, अतः प्रकरण को समय सीमा में मानकर धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे तथा यदि व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकालकर कर निर्धारण किया जाता है तो व्यवहारी को यदि कोई इनपुट टैक्स नियमानुसार देय होता है तो उसका लाभ भी दिया जाये। व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.10.18 को उपस्थित हो।

16. निर्णय सुनाया गया।

(^{नल्लूराम}
नल्लूराम)
सदस्य